दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, सोमवार 28 जून 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 268

महत्वपूर्ण एवं खास

पुलिस ने 50 करोड़ रुपये के जब्त नशीले पदार्थों को किया नष्ट

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक सरकार ने मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने के चलते गांजा, पोस्ता, एलएसडी, एमडीएमए और करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन सहित जब्त पदार्थों को नष्ट कर दिया। कर्नाटक ने पिछले साल ड्रग्स के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया था, तब से पुलिस ने लगभग 50 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स को जब्त कर लिया था और इसमें से 60 प्रतिशत को अदालतों की मंजूरी के आधार पर नष्ट कर दिया गया है। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि जब भी एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की रिपोर्ट आएगी और कोर्ट इसकी इजाजत देगा, बाकी 40 फीसदी भी नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मौजूदा नियमों में उपयुक्त संशोधन लाने से इस खतरे को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के हाथ और मजबूत होंगे।

यूपी के रामपुर में कार नाले में गिरी, चार लोगों की मौत

रामपुर (आरएनएस)। दिल्ली से नैनीताल जा रही एक कार के नाले में गिर जाने से चार लोगों की मौत हो गई । रामपुर के एएसपी ने बताया कि थाना गंज पुलिस को सूचना मिली कि एक गाड़ी नाले में गिर गई, पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार 4 लोगों को मौत हो गई। ये लोग दिल्ली से नैनीताल जा रहे थे।

विरोध प्रदर्शन को लेकर लाखा सिधाना समेत अन्य पर मामला दर्ज

चंडीगढ़ (आरएनएस)। बैरिकेड्स तोड़कर और पानी की बौछारों का सामना करने के बाद हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के चंडीगढ़ में प्रवेश करने के एक दिन बाद, स्थानीय पुलिस ने आज गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने लखवीर सिंह उर्फ लाखा सिधाना और कीर्ति किसान यूनियन के उपाध्यक्ष राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेक्टर-17 थाने में आईपीसी की धारा 186, 188, 332, 353, 147, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि पंजाबी गायक जस बाजवा और अभिनेत्री सोनिया मान के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है, जो विरोध मार्च का हिस्सा थे।

गोवा में कोविड कर्फ्यू 5 जुलाई तक बढ़ा

पणजी (आरएनएस)। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए कर्फ्यू को पांच जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की। सावंत ने ट्वीट किया, गोवा सरकार ने राज्य स्तरीय कर्फ्यू को 5 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण और मौतों की वृद्धि के मद्देनजर राज्य स्तर पर पहली बार 9 मई को कर्फ्यू लगाया गया था। बाद में समय-समय पर छह बार बढ़ाया गया।

ईडी ने अवैध कोयला तस्करी मामले में 6 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने अवैध कोयला खनन के संबंध में वेस्ट एंड पिगमेंट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स देशप्रान प्रॉपर्टीज लिमिटेड के संयुक्त स्वामित्व वाली 6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। संपत्ति को अवैध कोयला खदान मामले के संबंध में कुर्क किया गया है, जो कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की युवा शाखा के नेता विनय मिश्रा से जुड़ी हुई है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोलकाता में दोनों कंपनियों के संयुक्त स्वामित्व वाले 6 करोड़ रुपये के एक भूखंड (प्लॉट) को कुर्क किया है। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि इस संपत्ति की खरीद के लिए 6 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि एलटीबी इंफ्राकंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते से ट्रांसफर की गई थी। अधिकारी ने कहा, आगे की जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त फंड का स्रोत अपराध की आय से था, जिसे एलटीबी इन्फ्राकंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में नकद में जमा किया गया था, जिसके मालिक विनय मिश्रा और विकास मिश्रा हैं।

उच्च न्यायालयों की सभी वेबसाइटों में अब दिव्यांगजनों के लिए हुआ कैप्चा उपलब्ध

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय न्यायिक प्रणाली के डिजिटल बुनियादी ढांचे को दिव्यांगजनों के लिए और अधिक सुलभ बनाने का कार्य पिछले कुछ महीनों के दौरान उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के काम का एक मुख्य घटक रहा है। इस उद्देश्य की दिशा में ई-समिति के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव यह सुनिश्चित करना है कि सभी उच्च न्यायालय की वेबसाइटों में अब दिव्यांगजनों के लिए कैप्चा सुलभ करा दिए गए हैं। ये कैप्चा न्यायालय की वेबसाइट के कई आवश्यक पहलुओं जैसे कि निर्णय / आदेश, वाद-सूचियाँ और मामलों की स्थिति की जांच तक पहुँचने के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय की कई वेबसाइटें अब तक विशेष रूप से नेत्रहीनों के लिए

निष्प्रयोज्य दृश्य कैप्चा का उपयोग कर रही थीं, जिससे उनके लिए ऐसी सामग्री को स्वतंत्र रूप से देख-समझ पाना असंभव हो गया था। सभी उच्च न्यायालयों के आपसी समन्वय से, ई-समिति ने अब यह सुनिश्चित किया है कि दृश्य कैप्चा के साथ शब्दों और श्रव्य कैप्चा भी होने चाहिए ताकि दृष्टिबाधित लोग भी ऐसी वेबसाइट की सामग्री को आवश्कतानुसार प्राप्त कर सके।

16 दिसंबर, 2020 के एक पत्र में, ई-समिति के अध्यक्ष, डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सभी उच्च न्यायालयों से दिव्यांगजनों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के अनुरूप उनके लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने का आह्वान किया था। पत्र में इस संबंध में सभी उच्च न्यायालयों के लिए प्रक्रिया में संरचनात्मक हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला भी शामिल की गई थी।

इस पत्र के बाद की प्रक्रिया अनुसरण में, ई-समिति ने इस परियोजना के पहले चरण में सभी उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों के डिजिटल इंटरफेस की सब तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की। यह जानने के लिए निम्नलिखित छह मानक तैयार किए गए थे कि उच्च न्यायालय की वेबसाइट सुलभ है भी या नहीं- निर्णयों तक पहुंच; कारण-सूचियों तक पहुंच; मामले की स्थिति तक पहुंच; कंट्रास्ट/रंग विषय; पाठ का आकार [ए + एए]; और स्क्रीन रीडर एक्सेस।

ई-समिति ने सभी उच्च न्यायालयों के केंद्रीय परियोजना समन्वयकों और उनकी तकनीकी टीमों के लिए जागरूकता पैदा करने और सभी उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों के डिजिटल इंटरफेस की पहुंच सुनिश्चित करने और सुलभ पीडीएफ बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की। उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें अब कुछ उन वेबसाइटों को छोड़कर उपरोक्त मापदंडों का अनुपालन करती हैं, जो स्क्रीन रीडर एक्सेस प्रदान करने की प्रक्रिया में हैं। इन मानकों के साथ उच्च न्यायालयों के अनुपालन की स्थिति- अनुलग्नक ए में दी गई है ।

ई-समिति सुलभ अदालती दस्तावेजों को तैयार करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की प्रक्रिया में भी है और अपने हितधारकों के लिए एक उपयोगी निर्देशिका के रूप में काम करेगी। यह वॉटरमार्क, हाथ से लिखने, गलत स्थानों पर टिकट चिपकाने और फाइलों में अनुपलब्ध पृष्ठों के मामलों का भी समाधान करेगा। इस संबंध में, ई-समिति के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ ने उक्त एसओपी तैयार करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को दिनांक 25.06.2021 को एक पत्र भी लिखा था।

एनआईसी के सहयोग से ई-समिति द्वारा की गई एक अन्य महत्वपूर्ण पहल दिव्यांगजनों के लिए सुलभ निर्णय खोज पोर्टल (https://judgments.ecourts.gov.in) बनाना है। पोर्टल में सभी उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और अंतिम आदेश शामिल किए गए हैं। पोर्टल एक निशुल्क टेक्स्ट सर्च इंजन का उपयोग करता है। इसके अलावा, पोर्टल टेक्स्ट कैप्चा के साथ ऑडियो कैप्चा का उपयोग करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह सुलभ कॉम्बो बॉक्स का भी उपयोग करता है, जिससे नेत्रहीनों के लिए वेबसाइट पर काम करना आसान हो जाता है।

जम्मू कश्मीर के बाद अब एक जुलाई को कारगिल और लद्दाख के नेताओं संग होगा मंथन

नई दिल्ली (आरएनएस)। गत 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू-कश्मीर के नेताओं के बीच बैठक हुई। वहीं अब केंद्र ने कारगिल और लद्दाख की पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करने की पहल की है। इसके तहत गृह मंत्रालय ने 1 जुलाई को कारगिल और लद्दाख के नेताओं और समाजसेवियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है।

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम की बैठक में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से कोई प्रतिनिधि नहीं था। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, यह उन बैठकों के क्रम में है जो मंत्रालय पिछले कुछ महीनों से लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ उनकी संस्कृति, भूमि और भाषा की सुरक्षा के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कर रहा है। इस संबंध में पहले लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी, लेकिन कारगिल के लोग एक अलग बैठक चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनकी चिंताएं अलग हैं। बैठक में राजनेता और नागरिक समाज के सदस्य दोनों शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के नेताओं से अपील की है कि लोगों को, खासकर युवाओं को जम्मू-कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व देना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी अपेक्षाएं पूरी हों। सर्वदलीय बैठक में आठ दलों के 14 नेता शामिल हुए थे।

देश में फिर नजर आई कोरोना मामलों में मामूली बढ़ोतरी

» 24 घंटे में मिले 50,040 नए केस, 1258 मरीजों ने गंवाई जान

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 50 हजार के पार आए और इसी दौरान 1258 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ दिया। इस दौरान 57,944 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के

मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अबतक कोरोना की वजह से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 3,95,751 हो गया है। जबकि मौजूदा समय में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,86,403 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.94 फीसदी हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर भी 96.75 फीसदी हो गया है और अब तक देश भर में अब तक कोरोना को मात देने वालों की कुल संख्या 2,92,51,029 हो गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.82 फीसदी हो गया है।

24 घंटों में 64.25 लाख टीके लगे- गौरतलब है कि ये लगातार 45वां दिन है जब ठीक होने वालों की संख्या दैनिक नए मामलों से अधिक है। कोरोना वायरस का वीकली पॉजिटिविटी रेट 5प्रतिशत से नीचे बनी हुई है और फिलहाल 2.91त्न पर है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 32.17 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 64.25 लाख टीके की खुराक दी गई। सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 31 जुलाई तक कोविड टीके की कुल 51.6 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें से 35.6 करोड़ खुराक पहले ही मुहैया करायी जा चुकी हैं। बच्चों के लिए टीका उपलब्ध कराने की स्थिति को लेकर केंद्र ने एक हलफनामे में कहा कि भारत के दवा नियामक ने 12 मई को भारत बायोटेक को उसके टीके कोवैक्सीन का क्लीनिकल ट्रायल दो से 18 साल के प्रतिभागियों पर करने की अनुमति प्रदान की थी और इस परीक्षण के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है।

देश के 12 राज्यों में मिला डेल्टा प्लस वैरिएंट

» फेफड़ों को बेहद तेजी से संक्रमित होने का खतरा

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वैरिएंट कई राज्यों में मिल गया है। इस पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन (एनटीएजीआई) के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोरा का कहना है कि कोरोना के बाकी वैरिएंट के मुकाबले, डेल्टा प्लस वैरिएंट फेफड़ों तक जल्दी और आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये वैरिएंट ज्यादा संक्रामक है या इससे गंभीर कोरोना हो सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के अब तक 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वैरिएंट के 51 मामले सामने आ गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दर्ज किए

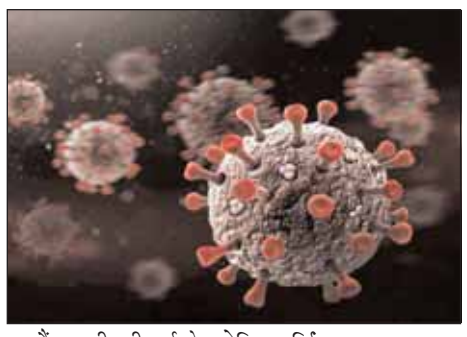

गए हैं। एनटीएजीआई के कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. एनके अरोरा ने कहा कि हालांकि डेल्टा प्लस वैरिएंट से फेफड़ो को नुकसान पहुंचता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है।

डॉ, अरोरा ने बताया कि डेल्टा प्लस वैरिएंट के प्रभाव पर स्पष्टता तब आएगी, जब इसके ज्यादा मामले सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि यह रोग आमतौर उन सभी लोगों में हल्का होता है, जो जिन्हें टीके की एकल या दोहरी खुराक मिली है। हमें इस पर नजदीकी से निगरानी रखनी होगी, तभी इसके संक्रमण के बारे में उचित जानकारी मिलेगी।

डॉक्टर अरोरा ने आगे कहा कि डेल्टा प्लस वैरिएंट के और भी मामले अभी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं होते, इसलिए इस वैरिएंट के बारे में जानकारी नहीं मिलती लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें मरीज में कोविड 19 के लक्षण तो नहीं है लेकिन उनमें डेल्टा प्लस वैरिएंट पाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि देश में अच्छी बात यह है कि इस वैरिएंट को लेकर जीनोम सिक्वेंसिंग पहले से ही की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस वैरिएंट को फैलने से रोकना है तो वैक्सीनेशन को और तेज करना होगा। हालांकि उन्होंने आगे यह भी कहा कि डेल्टा प्लस वैरिएंट तीसरी लहर का कारण बनेगा, ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगा। डॉक्टर अरोरा ने आगे कहा कि देश में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर जारी है और पिछले आठ से दस दिनों से दैनिक मामले 50 हजार के आसपास ही आ रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अगर हम वैक्सीनेशन को तेज कर देंगे, तो तीसरी लहर की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कोरोना की वैक्सीन के साथ-साथ मास्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

12-18 साल के बच्चों का अगले एक माह में होगा टीकाकरण

» जायडस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत को जल्द ही एक और हथियार मिलने वाला है। कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉ एनके अरोड़ा ने कहा है कि जायडस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। जुलाई के अंत तक या अगस्त में, हम 12-18 आयु वर्ग के बच्चों को यह टीका देना शुरू कर सकते हैं। एनके सिंह ने कहा कि आईसीएमआर एक स्टडी लेकर आया है जिसमें कहा गया है कि तीसरी लहर देर से आने की संभावना है। हमारे पास देश में हर किसी का टीकाकरण करने के लिए 6-8 महीने की विंडो अवधि है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य हर दिन 1 करोड़ खुराक देने का है। एनके अरोडा ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोग सक्रिय रूप से आगे आएं और टीके लें, यह नितांत आवश्यक है। कई अफवाहें हैं, गलत सूचना जो देश में फैल रही है। इसी तरह लोगों के मन में कुछ अस्पष्ट भय रहता है। उन्हें लगता है कि कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं या टीका असुरक्षित हो सकता है। अरोड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस के अन्य स्वरूपों की तुलना में डेल्टा प्लस स्वरूप का फेफड़ों के उत्तकों से ज्यादा जुड़ाव मिला है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इससे गंभीर बीमारी होगी या यह ज्यादा संक्रामक है।

योग के साथ रिकार्ड वैक्सीन ने दुनिया को दिखाई भारत की ताकत : पीएम मोदी

» मन की बात की बात में कोरोना वैक्सीन के लिए किया लोगो को प्रेरित

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित कर रहे है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह को याद करते हुए कहा कि, कुछ दिन पहले कोरोना ने प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह को हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे, तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि,बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट का मनोबल बढ़ाना है। आगामी तोक्यो ओलंपिक को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि, टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे हैं बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाडियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। मन की बात के 78 वें एपिसोड को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना टीकाकरण पर भी जोर दिया और ग्रामीण इलाकों में जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन अभियान को तेजी से बढ़ाने का आह्वन किया और कहा कि,कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया..वो भी एक दिन में।

पीएम मोदी ने कहा कि एक साल पहले सबके समाने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी? आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं। यही तो नए भारत की नई ताकत है। कभी-ना-कभी ये विश्व के लिए केस स्टडी का

विषय बनेगा कि भारत के गांव के लोगों, हमारे वनवासी-आदिवासी भाई-बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटीन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए।

मानसून सीज़न पर पीएम मोदी ने कहा कि, हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं बरसते बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकठ्ठा होता है,जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है इसलिए मैं जल सरंक्षण को देश सेवा का एक ही रूप मानता हूं।पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि, 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाएंगे। ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेट्समैन डॉक्टर बीसी राय की जन्म-जयंती को समर्पित है। कोरोना-काल में डॉक्टरों के योगदान के हम सब आभारी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है।